शिक्षा : दूरगामी निर्णयों की ज़रूरत

विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन और कुछ राष्ट्रों से भारत ने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्जा ले रखा है। कई संगठनों और सरकारों से शिक्षा के लिए प्राप्त रुपयों को खपाने के लिए देश में कई तरह की शिक्षा योजनाएँ चल रही हैं। इनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, गुरु मित्र योजना, शिक्षक समाख्या, शिक्षा गारण्टी योजना, सर्वशिक्षा, जनशाला, मुक्तांगन, आँगनबाड़ी, सतत शिक्षा, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा और कई तरह की शिक्षा योजनाएँ सम्मिलित हैं। ये सभी योजनाएँ कर्ज लेकर अथवा गरीबों पर लगाये टैक्स के रुपयों से संचालित हैं और सभी, शिक्षा के सार्वजनीकरण के प्रयासों में रुपया बहा रही हैं। देश में 1992-93 के सर्वेक्षण के मुताबिक 6 से 14 आयुवर्ग में 2 करोड़ 30 लाख लड़के व 3 करोड़ 70 लाख लड़कियाँ स्कूल से नहीं जुड़ पाई हैं। कुल छ: करोड़ पढ़ने योग्य बच्चे स्कूलों से वंचित हैं जबकि 83 वें संविधान संशोधन के जरिये 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए कवायद अभी जारी है। 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए पचासों योजनाएँ हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि किसी एक ही राज्य में शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए दसों तरह की योजनाएँ चल रही है। किसी एक ही जिले व एक ही गाँव में अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग अधिकारी और उनकी अलग-अलग रिपोर्टें है। अगर सभी रिपोर्टों को देखें तो पता लगेगा कि किसी एक ही बच्चे का तीन-चार एजेंसियों में नाम दर्ज है जबकि वह पाँचवीं जगह किसी निजी शिक्षाशाला से जुड़ा होगा। इस तरह से शिक्षा में पूर्ण अराजकता व्याप्त है। शिक्षा में एक नया माफिया अवतार ले चुका है।

वस्तुत: शिक्षा के लिए सभी योजनाओं के 'एकीकरण' की ज़रूरत है। देखा गया है कि एक योजना का विशेषज्ञ किसी दूसरी, तीसरी योजना के लिए काम करते समय अतिरिक्त भारी राशि ग्रहण करता है। ऐसे में अगर पूरे देश अथवा राज्य में सिर्फ एक योजना हो तो अतिरिक्त पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से कई तरह की कार्ययोजनाएँ समान होती हैं जिनमें एक ही काम के लिए अलग-अलग योजनाएँ अलग-अलग धन खर्च करती हैं। इसके साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कोई दीर्घ कार्ययोजना नहीं है। शिक्षा के लिए सरकार को रात में कोई सपना आया, सुबह लागू कर दिया। कोई चिन्तन नहीं, कोई विचार नहीं। बस काम करते जा रहे हैं। रिपोर्टें बनाई जा रही हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद् पॉलो फ्रेरे ने इस स्थिति को 'सक्रियतावाद' कहा है। काम किया जा रहा है बिना किसी ठोस चिन्तन के। बिना कोई स्पष्ट विचारधारा के।

अगर यही अलग-अलग राग और पलभर की सोच की पूर्ति करनेवाली योजनाएँ रहीं तो गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए आगामी पचास वर्षों के लिए भी एक स्वप्न ही बनी रहेगी। एक ही राज्य और एक ही देश के लिए संचालित की जा रही शैक्षिक योजनाओं को समाकलित करके शिक्षा के लिए समन्वित प्रयास की ज़रूरत है। इसी समन्वित प्रयास की सघनता और तीव्रता के सहारे ही अशिक्षा पर काबू पाया जा सकता है। **साथ ही किये जा रहे प्रयासों के निर्णयों पर गहरे शैक्षिक विमर्श की आवश्यकता है।** समय-समय पर केवल मैकाले को गाली देने से बेहतर है हम आज के सन्दर्भ में शिक्षा के नये आयाम प्रस्तुत करें। सौभाग्य से 2001 की जनगणना के साथ कई तरह की गणना से देश के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर चिन्तन करने की स्पष्ट दिशा मिल सकेगी। अत: शिक्षा को जीवनोपयोगी व जीवन के आनन्द के लिए प्रस्तुत करने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना व उन पर चलना नितान्त ज़रूरी होगा। हम दीर्घ अवधि का लक्ष्य ही रखें मगर दूरगामी विचार आवश्यक है।

✍ **रामविलास जांगिड़**
66/138, वी टी रोड, मानसरोवर, जयपुर - 302020
(साभार : राजस्थान पत्रिका)

किसी कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लग जाना ही सफलता की पहली शर्त है।
-वी.एन. लाल

सौजन्य : श्री निर्मल भण्डारी, हैण्डीक्राफ्ट निर्यातक, जोधपुर